भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3341

28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना

3341# श्री संजय सिंह:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस्पात उत्पादन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष पहल या योजना अपना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि चीन और अन्य देशों से सस्ते दरों पर इस्पात के आयात के कारण घरेलू इस्पात उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और यदि हां, तो घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) से घरेलू इस्पात उद्योग की सुरक्षा के लिए सरकार क्या उपाय करने की योजना बना रही है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और कंपनी की स्थिरता, आयात तथा निर्यात बाजार शक्तियों के अतिरिक्त विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होते है। सरकार घरेलू इस्पात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने हेतु अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित करके एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। इस संबंध में किये गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:-

i. आयातित इस्पात उत्पादों जो घरेलू इस्पात उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर करते हैं, पर पाटन रोधी शुल्क (एडीडी) और प्रतिकारी शुल्क (सीवीड़ी) लगाना।
ii. लौह मिश्रधातु, लौह स्क्रैप जैसे कच्चे माल जो देश में पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हैं, पर आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) का आवधिक अंशांकन।
iii. आयात की प्रभावी निगरानी और घरेलू इस्पात उत्पादकों को आयात पर विस्तृत आंकडे उपलब्ध कराने के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) 2.0 को नया रूप दिया गया।
iv. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने हेतु घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।
v. देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा आयात को कम करने के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को शुरू करना।

जारी...2/-

vi. घरेलू स्तर पर उत्पन्न लौह स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

vii. सरकार ने ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया रोडमैप एंड एक्शन प्लान नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करके इस्पात उद्योग मे अकार्बनीकरण की दिशा में पहल की है और साथ ही 'ग्रीन स्टील के लिए वर्गीकरण' भी जारी किया है।

*****